((घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के सुचारू कार्यान्यव के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि से कितनी सहायता प्राप्त की गई है और अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई, और

(ड़) क्या सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर कोई समीक्षा की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री ए0 आर0 अंतुले) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को संस्थागत बनाना है । इस नीति के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा के, प्रौढ़ शिक्षा पद्धति औरउच्चतर शिक्षा पद्धति में जनसंख्या शिक्षा शुरू की गई है । श्रम मंत्रालय के माध्यम से एक व्यवसाथिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में जनसंख्या शिक्षा पर एक परियोजना भी शुरू की जा चुकी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान यू0 एस0 एफ0 पी0 ए0 से प्राप्त की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

		92-93	93-94	94-95
(i)	स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा में राष्ट्रीय	67.96	75.00	70.00
(ii)	उच्चतर शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीय	66.25	28.40	22.42
(iii)	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना	71.51	67.68	89.00

1980 से क्रम सं0 (i), (ii) और (iii) की परियोजना ने अपने कार्यानवयन के दों चक्र पूरे कर लिए हैं और अपने तीसरे चक्र में चल रही है । तथापि, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण जनवरी, 1996 से शुरू हो चुका है ।

(ड़) कार्यान्वयन करने वाले संबंधित अभिकरणों द्वारा इस परियोजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

रेल डिब्बों की आवश्यकता

853.**श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

Complaints against ITDC Officials

852. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) how many officials were charge sheeted during the last three years in ITDC;

(b) the complaints/memorandum received by Government/ITDC in the p;ist from Trade Unions/Members of Parliament / other Organisations regarding Senior Officials of ITDC in New Delhi;

(c) what is the content of each complaint, their date of receipt, action taker/initiated and by when each complaint will be disposed of; and

(d) what remedial measures are being taken by Government to get rid of officials of doubtful intergrity?

THE MINISTER OF CIVIL AVAITION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) During the last three years i.e. 1993, 1994 and 1995 a total number of 424 employees were issued charge sheets.

(b) to (c) Information is being collected.

(d) Action against officials of proven doubtful integrity is taken prescribed rulc&procedure.

7c* fesgjf 5ft 34ltfy!f*HI

853. sft faimrrf jfwrf ^pFt: *wfi* TOR *m*\ Ti* *raft ti ^ #r fe

(क) पश्चिम रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने रेल डिब्बों की आपूर्ति की गयी,

(ख) चालू वित्तीय वर्ष मे पश्चिम रेलवे को कितने रेल डिब्बों की आवश्यकता है और क्या पश्चिम रेलवे ने रेलडिब्बों की आपूर्ति के लिए अपना मांग-पत्र दिया है, और

(ग) यदि पश्चिम रेलवे ने अभी तक अपना मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) :

(क)	1992-93	306
	1993-94	186
	1994-95	244
	1995-96	250 (जनवरी तक)

(ख) और (ग) हरेक रेलवे नए सवारी डिब्बों के निर्माण और आपूर्ति के लिए आर्डर नहीं देती है। रेल मंत्रालय सेवा से हटाए जाने वाले सवारी डिब्बों तथा नई सेवाएं शुरू करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सवारी डिब्बों को ध्यान में रखते हुए सभी रेलों के लिए किसी विशेष वर्ष में सवारी डिब्बों की आवश्यकता को समेकित करता है । तदनुसार पश्चिम रेलवे सहित प्रतयेक रेलवे को सवारी डिब्बों का आवंटन किया जाता है।

विमानचालकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि

854. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान चालकों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के संबंध में किसी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है, यदि हां, तो वेतन और भत्तों में कितने प्रशित वृद्धि को जायेगी और यह कब से, किस कारण और किस आधार पर लागू होगी,

(ख) क्या सरकार ने विमान चालकों के वेतन और भत्तों में वृत्ति के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा और उचित सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये हैं, और

(ग) विमानचालकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि के बावजूद भी उनके द्वारा हड़ताल किये जाने पर या सामूहिक अवकाश लिये जाने परे अन्यथा कठिन स्थिति उत्पन्न करने पर सरकार लिये जाने पर अन्यथा कठिन स्थिति उत्पन्न करने का सरकार क्या कार्रवाई करेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां। इंडियन एयरलाइन्स ने भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 01.01.96 से प्रभावी होगा। अन्य बातों के साथ-साथ, समझौते के अन्तर्गत उड़ान के घंटों के आधार पर विमानचालकों को किए जाने वाले भुगतान की पद्धति को युक्तिसंगत बनाना, उनका प्रशिक्षण और विमान बेड़े का बेहतर उपयोग भी शामिल हैं। विमानचालकों के वेतन में औसतन 85% के लगभग वृद्धि होगी।

(ख) सेवाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया हैं । इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में यात्रियों का आराम, उड़ानगत तथा भूमि पर सेवाएं शामिल हैं।

(ग) समझौते में, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने हड़ताल न करने तथा संवैधानिक तरीके अपनाने का वचन दिया है । तथापि, आवकश्यता होने पर प्रबंधकवर्ग कम्पनी के विनियमों तथा स्थाई आदेशों के तहत उचित कार्रवाई करेगा।

Investment by Government undertakings

855. SHRI S AR AD A MOHANTY: Will the Ministry of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of investment made by different Central Government undertakings in the Industrial sector during Seventh and Eighth Plan; and

(b) the achievement of each undertaking during that period in terms of production to meet domestic demand, export potentiality and employment generation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVER A): (a) and (b) The details of investment made in each Central Government Public Sector Undertaking and their achievement in terms of production (sales turnover) and employment generation is given in Volume-Ill of the 'Public Enterprises Survey' placed on the Table of both the Houses of Parliament every year. The latest Public Enterprises Survey laid in Parliament on 22nd March, 1995 contains the information for the year 1993-94, 1992-93 and 1991-92. Export earning by different Public Sector Undertaking is given in Statement No. 24 of Volume-I of Public Enterprises Survey.